

अग्र भारत

नई सोच का अखबार

www.agrabharat.in

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्षः 19 | अंकः 125 | आगरा, शनिवार 24 अक्टूबर 2026 | पृष्ठः 8 मूल्यः 2.00 रू.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ाने कई कारक करते हैं एक साथ काम

नई दिल्ली (ए)। दिल्ली-एनसीआर में हर साल अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत होते ही वायु प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ने लगता है। दिल्ली की हवा इस महीने में जहरीली क्यों हो जाती है, इसके पीछे कई कारक एक साथ काम करते हैं, जिनमें भौगोलिक स्थिति, मौसमी बदलाव, वाहनों का धुआं, पराली जलाना और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल शामिल हैं।

आसमान में धुंध छा जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) कई इलाकों में खराब से गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने की सबसे बड़ी वजहों में से एक तापमान संबंधी उलटाव यानी थर्मल इन्वर्जन है। सामान्य परिस्थितियों में गर्म हवा ऊपर उठकर प्रदूषक कणों को अपने साथ ले जाती है, लेकिन सर्दियों में जमीन के पास ठंडी हवा और उसके ऊपर गर्म हवा की परत बन जाती है। यह स्थिति प्रदूषकों को ऊपर की ओर फैलने से रोकती है, जिससे धूल,



धुआं और जहरीले कण जमीन के करीब जमा होते रहते हैं।

दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी इस समस्या को गंभीर बनाती है; मुंबई या चेन्नई जैसे तटीय शहरों के विपरीत, दिल्ली समुद्र से दूर है। सर्दियों में यहां हवा की गति कम होने पर प्रदूषक लंबे समय तक वातावरण में जमे रहते हैं। नवंबर के दौरान पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं भी दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर बड़ा असर डालती हैं। धान की कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेषों को जलाने से निकलने वाला धुआं, हवा की दिशा अनुकूल होने पर दिल्ली तक पहुंच सकता है। हालांकि, इसका प्रभाव पराली जलाने की घटनाओं की संख्या और हवा की दिशा व गति पर निर्भर करता है। दिल्ली में वाहनों की बड़ी संख्या, औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि करती हैं। पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन के अलावा, सड़कों की धूल और निर्माण स्थलों के सूक्ष्म कण हवा में मिलकर प्रदूषण को बढ़ाते हैं।

दिवाली के आसपास पटाखों का धुआं और सूक्ष्म कण भी पहले से प्रदूषित हवा की स्थिति को और खराब कर सकते हैं। जब ठंड बढ़ती है, हवा शांत रहती है और क्षेत्रीय प्रदूषण (जैसे पराली का धुआं) भी पहुंचता है, तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नवंबर में प्रदूषण केवल दिल्ली में नहीं बढ़ता है, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित उत्तर भारत के कई शहर इस समस्या से प्रभावित होते हैं। दिल्ली की समस्या इसलिए अधिक चर्चा में रहती है क्योंकि यहां स्थानीय उत्सर्जन, क्षेत्रीय प्रदूषण और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां एक साथ मिलकर घातक प्रभाव डालती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केवल पराली जलाने पर रोक लगाना पर्याप्त नहीं है।

दाऊद इब्राहिम को भारत में रहने वाला बताने पर भड़का भारत, यूएन रिपोर्ट का किया विरोध

नई दिल्ली,(ए)। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के एक विशेष विशेषज्ञ की रिपोर्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन और वांछित आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को भारत में रहने वाला दिखाने पर भारत ने बेहद कड़ा एतराज जताया है। भारत ने रिपोर्ट को तथ्यों से परे और पूरी तरह से भ्रामक बताकर कहा है कि इस तरह की गंभीर गलतियां संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था की साख को भारी नुकसान पहुँचाती हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघु पुरी ने मानवाधिकार मामलों के विशेष रिपोर्टर बेन सॉल की रिपोर्ट की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने में घोर अयोग्यता और लापरवाही दिखाई गई है। रिपोर्ट में दाऊद की डी-कंपनी को भारत-आधारित आपराधिक गिरोह बताया गया था। इस पर भारत ने स्पष्ट किया कि दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद ही भारत से भाग चुका था और 2003 में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बहुत पहले ही देश छोड़ चुका था।



रघु पुरी ने रिकॉर्ड दुरुस्त कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के दस्तावेजों में यह साफ तौर पर दर्ज है कि दाऊद भारत में वांछित है और वह उसी देश (पाकिस्तान) में शरण लिए हुए है, जहाँ अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ मिला था। भारत के अनुरोध पर उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। इसके बावजूद, विशेष रिपोर्टर द्वारा दाऊद के पाकिस्तान में होने के तथ्य को छुपाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गौरतलब है कि यूएन वॉच के अनुसार, रिपोर्ट तैयार करने वाले बेन सॉल को चीन सहित कई विदेशी संस्थाओं से भारी फंडिंग मिली है, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने उम्मीद जाहिर की कि यूएन के पदाधिकारी पारदर्शिता और ईमानदारी के मानकों का पालन करे। इसी मंच से भारत ने कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पुरी ने कहा कि पाकिस्तान की सेना और उसके हुक्मरान संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए भारत विरोधी झूठा प्रचार कर रहे हैं।

पंजाब में फिर परवान चढ़ेगा अकाली-भाजपा गठबंधन?

गृह मंत्री अमित शाह के बयान से गरमाई सियासत

नई दिल्ली,(ए)। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर पुराने राजनीतिक समीकरणों के लौटने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। साल 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े दावे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शाह के इस बयान के बाद कि आगामी चुनाव में पंजाब में एनडीए की सरकार बनेगी, यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर से हाथ मिला सकते हैं।

दरअसल दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया कि पंजाब की जनता अब बदलाव का पूरा मन बना चुकी है और राज्य में एनडीए की सरकार का गठन होगा। हालांकि, अपने इस बयान में शाह ने शिरोमणि अकाली दल के साथ औपचारिक गठबंधन को लेकर कोई सीधी घोषणा तो नहीं की, लेकिन उनके इस संकेत ने दोनों दलों के बीच संभावित पुनर्मिलन की अटकलों को



हवा जरूर दे दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंजाब में अकाली दल भाजपा का सबसे पुराना और पारंपरिक सहयोगी रहा है, ऐसे में बिना किसी बड़े तालमेल के एनडीए का रास्ता आसान नहीं होगा।

कृषि कानूनों के चलते टूटा था गठबंधन

गौरतलब है कि भाजपा और अकाली दल के बीच करीब 24 साल पुराना मजबूत गठबंधन सितंबर 2020 में उस समय टूट गया था, जब केंद्र सरकार के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर राज्य में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उस वक्त किसानों के समर्थन में अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था।

गठबंधन हुआ तो चुनाव होगा दिलचस्प

इस अलगाव का असर उसके बाद के चुनावों में साफ देखने को मिला। साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने एक-दूसरे से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिससे दोनों का जनाधार भी प्रभावित हुआ था।

'बड़े बदलाव सड़कों के संघर्ष से आए हैं', जंतर-मंतर आंदोलन पर बोलीं नेहा बोरा

नई दिल्ली (ए)। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा है कि देश में बड़े बदलाव हमेशा सड़कों पर हुए संघर्षों से आए हैं। आंदोलन केवल अपनी मांगों को पूरा कराने तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे लोगों को जागरूक करने और सत्ता से सवाल पूछने की ताकत देते हैं। जंतर-मंतर पर हुए आंदोलनों, छात्र राजनीति, लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक खास बातचीत में उन्होंने अपनी राय रखी।

नेहा बोरा ने कहा कि विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों का जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरना अच्छी बात है। उनके मुताबिक, विपक्ष को हमेशा लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करना चाहिए। कांग्रेस के साथ भविष्य में राजनीतिक तालमेल के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि आइसा की अपनी विचारधारा और राजनीतिक पहचान है। हालांकि, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में विभिन्न संगठनों और दलों का साथ आना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन सहित कई आंदोलनों ने दिखाया है कि जनसंघर्ष बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। किसी आंदोलन के बाद संबंधित पद पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति हो जाने से उसके प्रभाव को खारिज नहीं किया जा सकता।

बोरा के अनुसार, जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों का असर छात्रों के बीच भी दिखाई दिया है। स्कूलों के विद्यार्थी अपनी प्रयोगशालाओं और डेस्क की खराब स्थिति जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने नालसर, रांची और बिहार में छात्रों के प्रदर्शनों का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि छात्र अपने अधिकारों और सुविधाओं को लेकर पहले से अधिक मुखर हो रहे हैं।

वामपंथी कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका पर उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना उनके लिए नई बात नहीं है। उनसे पहले की पीढ़ियों ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक माहौल और न्यायिक टिप्पणियों को भी लोकतंत्र से जुड़ी व्यापक बहस का हिस्सा बताया।

चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नेहा बोरा ने कहा कि केवल किसी एक चुनाव आयुक्त के हटने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने और इससे प्रभावित बताए जा रहे 13 करोड़ लोगों के मतदान अधिकार बहाल करने की मांग की। उन्होंने 2023 के उस कानून पर भी सवाल उठाए, जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। उनके अनुसार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के बुनियादी आधार हैं।

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में गर्मी और उमस से लोग परेशान, जानें मौसम का हाल

मुंबई, (ए)। देशभर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं ठंड की आहट महसूस होने लगी है, तो कहीं भारी बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आसपास बन रही चक्रवाती हवाओं की स्थिति के कारण 23 अक्टूबर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। इस मौसमी प्रणाली के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और मजबूत होने की आशंका है। इसके चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं।

मुंबई और ठाणे में गर्मी और उमस का असर

एक ओर दक्षिण भारत में बारिश का दौर तेज होने की संभावना है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तापमान अधिक रहने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, घाट क्षेत्रों और दक्षिण कोंकण के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।

महाराष्ट्र को चक्रवात से कितना खतरा?

बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही मौसमी प्रणाली पर मौसम विभाग की नजर है। हालांकि, उपलब्ध पूर्वानुमान के आधार पर महाराष्ट्र की ओर किसी बड़े चक्रवात के सीधे बढ़ने का आधिकारिक संकेत नहीं है। इसलिए फिलहाल राज्य में चक्रवात का खतरा बताना उचित नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव और कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी रह सकती है। अरब सागर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में सोमालिया के तट के पास कम दबाव की एक प्रणाली का भी उल्लेख किया गया है।

अखिलेश ने कहा- कांग्रेस से मिली सीटों पर अंतिम फैसला आजम खां करेंगे

लखनऊ,(ए)। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में रामपुर जेल में पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से प्राप्त सीटों की सूची पर गहन मंथन करना था। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि प्रत्याशियों के चयन और सीटों के बंटवारे का अंतिम फैसला आजम खां की राय पर ही आधारित होगा।

एक घंटे से अधिक चली इस महत्वपूर्ण चर्चा ने एक बार फिर मोहम्मद आजम खां के पार्टी के रणनीतिक और नीतिगत फैसलों पर उनके अटूट प्रभाव को उजागर किया है, भले ही वे लंबे समय से सलाखों के पीछे हों। जेल से बाहर निकलने पर अखिलेश का यह बयान कि आजम थे, आजम हैं और आजम ही रहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। सियासी गलियारों में इसे सपा मुखिया द्वारा वेस्ट यूपी और रुहेलखंड के सियासी समीकरणों को साधने का एक मास्टरस्ट्रोक भी कहा जा रहा है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में खुलकर स्वीकार किया कि इंडिया गठबंधन के तहत मिली सीटों की लंबी सूची पर आजम खां के साथ गंभीर रायशुमारी हुई है। उन्होंने



कहा कि आजम खां द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को पूरी तरह से माना जाएगा, उन पर काम किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी।

यह पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे पर आजम खां से जेल में सलाह ली हो। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी अखिलेश ने सीतापुर जेल में आजम से मुलाकात कर टिकटों पर अंतिम मुहर लगाई थी। उस सीतापुर मॉडल का परिणाम यह रहा था कि 2022 के चुनाव परिणामों में मुरादाबाद मंडल की 27 विधानसभा सीटों में से 17 पर सपा ने परचम फहराया था। मुरादाबाद मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक आंकड़ों पर नजर डालें तो आज भी वहां सपा की मजबूती के पीछे आजम खां के जनाधार का सीधा प्रभाव दिखाई देता है। पत्रकारों द्वारा रामपुर सीट से सपा के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर, अखिलेश ने अपनी चिर-परिचित मुस्कान के साथ चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हें क्यों बताऊं? उनके इस छोटे से जवाब ने सियासी सस्पेंस को और गहरा दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, आजम खां की यह रणनीतिक सलाह सपा के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

मोदी सरकार 4 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाकर 75 प्रतिशत करेगी

नई दिल्ली(ए)। मोदी सरकार ने चार प्रमुख सरकारी बैंकों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 प्रतिशत करने की तैयारी कर ली है। इस पहल के तहत इन बैंकों के 25 प्रतिशत शेयर आम निवेशकों और अन्य शेयरधारकों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। यह महत्वपूर्ण कदम बाजार नियामक सेबी के उस अनिवार्य नियम का पालन करने के लिए उठाया जा रहा है, जिसके अनुसार शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत शेयर आम जनता के पास होना आवश्यक है।

फिलहाल, इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी काफी अधिक है। इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार के पास लगभग 92.44 प्रतिशत, यूको बैंक में 90.95 प्रतिशत, पंजाब एंड सिंध बैंक में लगभग 93.85 प्रतिशत और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 81.19 प्रतिशत शेयर हैं। सरकार की योजना है कि अगले एक साल में इन बैंकों में आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। इसके लिए बैंक खुद बाजार से पूंजी जुटा सकते हैं, या सरकार भी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने कुछ शेयर बेच सकती है।

हालांकि, बैंकों ने वित्त मंत्रालय से इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय मांगा है। बैंकों का मानना है कि मौजूदा बाजार परिस्थितियों में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी बेचना आसान नहीं होगा। शेयर बेचने का समय और तरीका अभी अंतिम रूप से तय होना बाकी है। सरकार की हिस्सेदारी घटाने की इस योजना को इन बैंकों के निजीकरण से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हिस्सेदारी बेचने का अर्थ यह नहीं है कि इन बैंकों का मालिकाना हक निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। हालांकि, यह सच है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं, और एक सरकारी थिंक टैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम निजीकरण के संभावित विकल्पों के तौर पर सुझाया था।

हमें कोई रोक नहीं सकता: पोलैंड के पीएम टस्क का बयान

नई दिल्ली (ए)। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं, जहाँ नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा विनिर्माण, व्यापार, उभरती प्रौद्योगिकियों, अंतरिक्ष अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा, दोनों शीर्ष नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) संबंधों जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत आगमन से ठीक पहले पोलैंड के प्रधानमंत्री ने एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए एक बेहद ऊर्जावान संदेश लिखा.....हमें कोई रोक नहीं सकता! अपने पोस्ट में उन्होंने भारत के साथ-साथ वियतनाम का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। टस्क ने लिखा कि वे अपने उप-प्रधानमंत्री और एक विशाल व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर भारत और वियतनाम में एक बड़ा आर्थिक अभियान शुरू कर रहे हैं। टस्क द्वारा वियतनाम का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा संपन्न करने के बाद वे 24 अक्टूबर को आधिकारिक दौरे पर सीधे वियतनाम रवाना हो रहे है। उनका यह संदेश स्पष्ट करता है कि पोलैंड वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से उभरते एशियाई देशों के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों का आक्रामक रूप से विस्तार करना चाहता है। प्रधानमंत्री टस्क का नई दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से टस्क का यह दौरा ऐतिहासिक है। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी दूसरी भारत यात्रा है; इससे पूर्व वे 2010 में भारत आए थे। वहीं, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारसॉ का ऐतिहासिक दौरा किया था, जिसके दौरान दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अपनी इस यात्रा के दौरान पोलिश प्रधानमंत्री दिल्ली के साथ-साथ देश की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु का भी दौरा करने वाले है। नई दिल्ली और बेंगलुरु में आयोजित भारत-पोलैंड बिजनेस फोरम में भाग लेने और सूचना प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात करने वाले है। उनके साथ आया उच्चस्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच एक भरोसेमंद और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) विकसित करने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशेगा।